



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1416]

नई दिल्ली, बंगलवार, अक्टूबर 7, 2008/आश्विन 15, 1930

No. 1416]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2008/ASVINA 15, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2421(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन डॉ. एच. टी. संगलिअना, संसद सदस्य के विरुद्ध दो गई याचिका पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का विनिश्चय :

श्री संतोष गंगवार, मुख्य सचेतक,

भारतीय जनता पार्टी, 2, संसद भवन, नई दिल्ली

—याची

बनाम

डॉ. एच. टी. संगलिअना, संसद सदस्य (लोक सभा)

दिल्ली का पता : बी-704, एम. एस. फ्लैट्स

बी. के. एस. मार्ग, नई दिल्ली-110001

स्थायी पता : फ्लैट संख्या 628, घाटप्रभा बी-4,  
नेशनल रोड्स हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स,  
बंगलौर - 560047 (कर्नाटक)

—प्रत्यर्थी

के मामले में

आदेश

1. यह लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य सचेतक श्री संतोष गंगवार द्वारा डॉ. एच. टी. संगलिअना, संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दायित्व याचिका है जिसमें 21 जुलाई, 2008 को लोक सभा में प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक की हैसियत से याची

द्वारा जारी पार्टी विधि का उल्लंघन करते हुए मतदान करने के कारण प्रत्यर्थी को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्थक करने संबंधी आदेश के लिए प्रार्थना की गई है।

2. याची द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी, जो लोक सभा का सदस्य है, बंगलौर उत्तर (कर्नाटक) निर्वाचन क्षेत्र से "भाजपा टिकट" पर निर्वाचित हुआ है तथा प्रत्यर्थी का नाम लोक सभा द्वारा प्रकाशित भाजपा सदस्यों की सूची में शामिल है।

3. याची के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने 18 जुलाई, 2008 को लोक सभा के अपने सभी सदस्यों, जिनमें प्रत्यर्थी भी शामिल है, को सभा में 21 और 22 जुलाई, 2008 को उपस्थित रहने और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने संबंधी तीन पंक्ति विधि जारी किया था। विधि की एक प्रति इस याचिका में दी गई है।

4. याची द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भाजपा, जिसके टिकट पर प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था, द्वारा उसे विधि जारी किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी ने पार्टी विधि और निदेश का धोर उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और इस तरह वह लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्थक हो गया है तथा यह कि पार्टी ने अपने निदेश के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए मतदान को माफ नहीं किया है।

5. प्रत्यर्थी ने याचिका के उत्तर में संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय को संबंधित दिनांक 4 अगस्त, 2008 के पत्र में यह तर्क दिया है कि "मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने श्री संतोष गंगवार से कोई ऐसा निदेश लिखित अथवा मौखिक रूप में प्राप्त नहीं किया है जैसा नियमों के नियम 6 के अधीन अपेक्षित है।" उसने यह भी तर्क दिया है कि आगे कार्रवाई करने के लिए उसे दिए गए निदेश का प्रमाण भेजा जाए।

6. प्रत्यर्थी के उत्तर के जवाब में, याची द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया गया है कि 20 जुलाई, 2008 को आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन सभी संसद सदस्यों को विपक्ष वितरित किया गया था जो बैठक में उपस्थित थे। प्रत्यर्थी ने उक्त बैठक में भाग लिया था और उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। याची ने आगे यह भी बताया कि विपक्ष जारी किए जाने के बारे में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से समाचार प्रकाशित हुए थे और विभिन्न न्यूज चैनलों ने इस संबंध में समाचार दिया था।

7. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) में यह उपबंध है कि पैरा 4 और 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निर्दिष्ट होगा जिसमें वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है, लिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है अथवा ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है। वर्तमान मामले में, पैरा 4 और 5 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

8. डॉ. गहानन्द प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं अन्य (2004) 8 एससीसी 747, के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अधीन "सभा के सदस्य की निर्दोशी के मुद्दे पर निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति या अध्यक्ष में निहित है। यह उल्लेखनीय है कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। उनको भूमिका कंवल संबद्ध तथ्यों को सुनिश्चित करने तक ही सीमित है। एक बार एकत्रित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि सभा के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1), (2), या (3) की परिधि में आता है, निर्दोशी लागू होगी और सभा के सभापति या अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा।"

9. मैंने राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया और 25 सितम्बर, 2008 को हुई सुनवाई में याची ने याचिका में दिए गए अपने तर्कों को दोहराया और याचिका के संदर्भ में प्रत्यर्थी की निर्दोशी के आदेश के लिए प्रार्थना की। प्रत्यर्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मेरे समक्ष यह निवेदन किया कि यद्यपि बैठक आयोजित की गई थी (उनके अनुसार 21 जुलाई को), याची समेत दल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई उल्लेख या चेतावनी या निर्देश नहीं दिया गया था कि प्रस्ताव पेश किए जाने पर प्रत्येक सदस्य को मतदान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि। उसने यह भी बताया कि "मैं यह नहीं समझता कि यह कहना उचित होगा कि बैठक में सामान्य घोषणा की गई थी कि राजग के सभी सदस्यों को उसके विरुद्ध मतदान करना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा, उस मामले में क्या करना है या क्या नहीं करना है, इस बारे में कोई ऐसी घोषणा या उल्लेख नहीं किया गया था।" प्रत्यर्थी ने यह भी तर्क दिया कि सार्वजनिक निर्देश किसी भी सदस्य के लिए व्यक्ति-विशिष्ट निर्देश नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उसे कोई नोटिस या निर्देश नहीं दिया गया था; और उसने यह भी बताया कि "यदि

असैनिक परमाणु करार पर राष्ट्रहित में मेरे मतदान से किसी दल विशेष या सरकार विशेष जो उस समय विशेष पर सत्ता में थी, को मदद मिली, तो मैं इसे संयोग मात्र मानता हूँ ... यह पूर्ण रूप से असैनिक परमाणु समझौता का मुद्दा था जिसके पक्ष में मैंने मतदान किया था ..."

10. अपने अगले निवेदन में, याची ने 20 जुलाई, 2008 को हुई बैठक का हवाला दिया जिसे विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने संबोधित किया था जिसमें मतदान के तरीके के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया था और यह बैठक केवल उसी मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी। याची ने आगे बताया कि प्रत्यर्थी ने उपस्थिति सूची में हस्ताक्षर किए थे और वह बैठक में उपस्थित था तथा वह बैठक की कार्यवाही के दौरान दिए गए निर्देश से पूर्णतः अवगत था।

11. अपने आगे के उत्तर में प्रत्यर्थी ने बताया कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी बैठक में हिन्दी में बोले थे तथा उस बैठक में कोई भी भाषान्तरकार नहीं था और "मैं नहीं समझ सकता था क्योंकि यह सब हिन्दी में था और जिसे मैं अच्छी तरह से बोलता और समझता नहीं हूँ।"

12. चूंकि वहां पर तथ्य के विवादास्पद प्रश्न थे, मैंने दोनों पक्षों से अनुरोध किया कि यदि वे चाहें तो शपथ ले सकते हैं तथा याची ने शपथपूर्वक पहले कही गई बात को दोहराया था तथा यह भी बताया कि मतदान की तारीख को वह प्रत्यर्थी की सीट पर गया तथा उससे प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने का अनुरोध किया था।

13. प्रत्यर्थी ने शपथपूर्वक कहा कि यह सच नहीं है कि याची ने उसे संसद भवन में निर्देश की एक प्रति दी थी। उसने कहा कि जब आरंभ में उसका मत रिकार्ड नहीं हुआ था तो श्री अरुण कुमार (भाजपा) तथा अन्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या हुआ है, उसके पास आए; तथा उन्होंने कहा: "मैं अभी भी यह सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए अर्थात् मेरी भर्षा ने काम नहीं किया था। अंत में, मैंने 'असैनिक परमाणु करार' के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया।" प्रत्यर्थी ने यह भी कहा कि "जो निर्णय मैंने लिया था वह देशभक्ति से अभिभूत था। मैंने असैनिक परमाणु करार के पक्ष में मतदान किया था न कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पक्ष में। इससे यदि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को कोई लाभ हुआ तो यह संयोग मात्र था।" वैयक्तिक सुनवाई के पूरा होने के पश्चात् प्रत्यर्थी ने दिनांक 30 सितम्बर, 2008 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने उस तर्क को दोहराया था कि यह अपेक्षित था कि याची को यह सिद्ध करना चाहिए कि निर्धारित निर्देश जारी किए गए थे और याची ने वैधानिक अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और यह कि याची यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि प्रत्यर्थी को कोई निर्देश दिया गया था।

14. वैयक्तिक सुनवाई की दलीलों और अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने 22 जुलाई, 2008 को प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। अब मुझे सिर्फ यह निर्णय करना है कि क्या प्रत्यर्थी को संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अनुसार कोई निर्देश जारी किया गया था।

15. विपक्ष एक निर्देश है जो राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों को विधानमंडल के समक्ष मुद्दे की जानकारी देने के लिए तथा उन्हें विपक्ष के अनुसार मतदान करने के लिए जारी किया जाता है।

विशिष्ट निर्देश जारी करने के अलावा, किसी महत्वपूर्ण अथवा विवादास्पद मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्यों, विशेष रूप से विधিনিर्माताओं और सामान्य तौर पर आम जनता को अवगत कराने की प्रत्याशा की जाती है। यह मानना गलत होगा कि किसी दल के सदस्यों को सदन के समक्ष किसी महत्वपूर्ण मामला आने पर उन्हें इस बात की जानकारी न हो कि अवसर विशेष पर उन्हें कैसे मतदान करना है।

16. तथापि, प्रायः यह सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक निर्देश दिया जाता है, विशेषकर दसवीं अनुसूची के अधिनियमन के बाद से, कि प्रत्येक सदस्य अपने दल की इच्छाओं और निर्देशों के अनुरूप कार्य करे।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *किहोता होलोहॉन बनाम जाचिलु और अन्य* (ए.आई.आर. 1993 उच्चतम न्यायालय 412) के निर्णय में यह टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के द्वारा यथा विचारित निर्देश लिखित रूप में सदस्यों को जारी किया जाना अपेक्षित है।

18. मेरी दृष्टि में, 'जारी किए गए निर्देश' जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) में दिया गया है, की व्याख्या करने में हमेशा यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सदस्यों को वास्तविक रूप में 'बिप' जारी करने की पावती पर उनके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिले। संबंधित सदस्य को वस्तुतः बिप जारी किए गए थे अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के क्रम में सभी परिस्थितियों और मामलों की सम्भाव्यता पर विचार करना होगा।

19. अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् तथा इस तथ्य पर विचार करने पर कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया है कि वह प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख से एक दिन पूर्व यानि 20 जुलाई, 2008 को दल की बैठक में उपस्थित था और यह कि शुरू में जब उसका मत रिकार्ड नहीं हुआ था, तो भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों ने सभा में उससे संपर्क किया था और इस मामले का तथा भाजपा, जिसका प्रत्यर्थी सदस्य है, द्वारा अपनाए गए रुख का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, मैं यह निर्णय लेने के लिए बाध्य हूँ कि प्रत्यर्थी को सभा में उपस्थित होने, चर्चा में भाग लेने तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने हेतु निर्देश जारी किया गया था। प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि यद्यपि वह 20 जुलाई, 2008 को आयोजित दल की बैठक में उपस्थित था तो भी वह उक्त बैठक में क्या हुआ, इसे समझ नहीं पाया क्योंकि वह हिन्दी नहीं जानता था।

20. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, अध्यक्ष को रूप में मेरा प्राथमिक कर्तव्य संगत तथ्यों का पता लगाना है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि प्रत्यर्थी ने अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान किया है, प्रत्यर्थी का कृत्य संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अंतर्गत आता है तथा मैं तदनुसार निर्णय लेता हूँ।

21. अतः, मेरा निर्णय है कि प्रत्यर्थी डॉ. एच. टी. संगलिंगना, जो बंगलूर उ्तर (कर्नाटक) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास मत के प्रस्ताव के लिए 22 जुलाई, 2008 को हुए मतदान में

उनके द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किए जाने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अंतर्गत निरह हो गए हैं।

22. इस प्रकार प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरह हो गया है और यह घोषित किया जाता है कि उसका स्थान रिक्त हो गया है।

नई दिल्ली

3 अक्टूबर, 2008

ह./-

सोमनाथ चटर्जी  
अध्यक्ष, लोक सभा

[सं 46/18/2008-टी]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

### LOK SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2008

S.O. 2421(E).—The following Decision dated 3 October, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:—

"Decision of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha on the petition given by Shri Santosh Gangwar, MP against Dr. H.T. Sangliana, MP under the Tenth Schedule to the Constitution

In the matter of:

Shri Santosh Gangwar, Chief Whip, BJP, 2, Parliament House, New Delhi.

—Petitioner

Versus

Dr. H. T. Sangliana, Member of Parliament (Lok Sabha) Delhi  
Address : B-704, M.S. Flats,  
B.K.S. Marg, New Delhi-110 001  
Permanent Address : Flat No. 628,  
Ghataprabha B-4, National Games  
Housing Complex, Bangalore-560047  
(Karnataka).

—Respondent

### ORDER

1. This is a petition filed by Shri Santosh Gangwar, Chief Whip of Bharatiya Janata Party (BJP) in Lok Sabha against Dr. H.T. Sangliana, MP, Lok Sabha praying for an order of disqualification of the Respondent from being and continuing as a Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule to the Constitution of India on account of his exercising his vote in violation of the party whip issued on him by the Petitioner as the Chief Whip of the BJP during the Motion of Confidence moved by the Prime Minister in Lok Sabha on 21 July, 2008.

2. It is contended by the Petitioner that the Respondent, who is a Member of the Lok Sabha, has been elected



from Bangalore North (Karnataka) constituency on the "BJP ticket" and the name of the Respondent appears in the list of BJP Members published by Lok Sabha.

3. According to the petitioner, the BJP, on 18 July, 2008 issued a three line whip to all its Members in Lok Sabha, including the Respondent to be present in the House on 21 and 22 July, 2008 and vote against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers. A copy of the whip has been set out in the Petition.

4. It is contended by the Petitioner that the Respondent, in spite of the whip having been issued to him by the BJP, on whose ticket the Respondent was elected to Lok Sabha, voted in favour of the Motion in gross violation of the party whip and direction and as such has incurred the disqualification for being a Member of the Lok Sabha and that his voting against the party's direction has not been condoned by the party.

5. The Respondent, by a letter dated 4 August, 2008 addressed to the Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, in reply to the Petition, has contended that "to the best of my knowledge I did not receive any such direction from Shri Santosh Gangwar either in writing or orally as required under rule 6 of the Rules." He has further contended that the proof of service of direction on him should be communicated to him to take further action.

6. A reply called replication has been filed by the petitioner in answer to the reply of the Respondent in which it has been contended that at a meeting of the BJP Parliamentary Party held on 20 July, 2008, a whip was distributed amongst all the MPs who attended the meeting. The Respondent attended the said meeting and also signed the Attendance Sheet. The Petitioner further stated that the news about the issuance of the Whip was widely published in the newspapers and reported by various news channels.

7. Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution provides that subject to provisions of paragraphs 4 and 5, a Member of the House belonging to any political party shall be disqualified for being a Member of the House, if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, without obtaining the prior permission of such political party or without obtaining the condonation of the political party for such voting or abstention within 15 days from the date of such voting or abstention. In the present case, the provisions of paragraphs 4 and 5 have no application.

8. In the decision of *Dr. Mahachandra Prasad Singh Versus Chairman, Bihar Legislative Council and others* (2004) 8 SCC 747, the Hon. Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule, "the final authority to take a decision on the question of disqualification of a Member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or

placed show that a Member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraphs (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect".

9. I gave opportunity of personal hearing to the parties and at the hearing held on 25 September, 2008, the Petitioner reiterated his contentions made in the petition and prayed for an order in terms of the petition for disqualification of the Respondent. The Respondent in his submission before me at the personal hearing submitted that although a meeting was held (according to him on 21st July), no mention or warning or direction was made by any party Member including the Petitioner saying that every Member should vote or should not vote when the Motion was moved etc. He further stated that "I do not think, it will be proper to say that the general announcement was made in the meeting that all the NDA Members should vote against that. To the best of my knowledge, as I said, there was no such announcement or mention about what to do or not to do in that issue." The Respondent further contended that a public direction is not an individual specific direction to a Member. The Respondent's case thus is that he was not served any notice or direction; and he further stated that "if my voting in the interest of the nation on the Civilian Nuclear Deal had helped a particular party or a particular Government, which was in power at that particular point of time, I consider it only incidental... It was purely on the issue of Civilian Nuclear Deal that I voted for..."

10. In his further submission, the Petitioner referred to a meeting held on 20 July, 2008 which was addressed by the Leader of the Opposition Shri L.K. Advani in which a clear direction was given regarding the manner of voting and that the meeting had been called only to discuss that issue. The Petitioner further stated that the Respondent had signed the Attendance Sheet, was present in the meeting and he was fully aware of the direction given during the proceedings of the meeting.

11. In his further answer, the Respondent stated that Shri L.K. Advani had spoken at the meeting in Hindi and there was no interpreter and that "I might not have understood because it was all in Hindi, which I do not very well speak or understand".

12. As there were disputed questions of fact, I requested both the parties to take oath for giving evidence, if they so desired and the Petitioner, on oath, reiterated his submissions made earlier and also stated that on the date of voting he had gone to the seat of the Respondent and had requested him to vote against the Motion.

13. The Respondent on oath stated that it was not factual that the Petitioner had given him a copy of the direction in the Parliament House. He said that when his vote had not been recorded initially, Shri Ananth Kumar (of BJP) and others came to him to ascertain what had happened; and he said: "I was still thinking what to do

when my machine did not work. Ultimately I decided to vote for the Civilian Nuclear Deal." The Respondent further added that "it was rather a patriotic decision that I took. I voted for the Civilian Nuclear Deal, not in favour of the UPA Government. If there was any favour for the UPA, it was just incidental." After the completion of the personal hearing, the Respondent submitted a letter dated 30 September, 2008 in which he reiterated the contention that it was required that the Petitioner should prove that the prescribed directions had been issued and that the Petitioner had not complied with the Constitutional requirement and that the Petitioner had failed to prove that any direction had been given to the Respondent.

14. From the pleadings and the records of the personal hearing, it is clear that the Respondent had voted in favour of the Motion on 22 July, 2008. The only question for me to decide now is whether the Respondent was issued any direction in terms of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution.

15. A Whip is a direction issued by Political parties to inform their Members of the issue before the Legislature and to direct them to vote in accordance with the Whip. Apart from issuance of specific direction, a stand taken by a political party on any important or contentious issue is expected to be known to its Members, specially the Legislators and also generally to the public at large. It is unreal to assume that the Legislators of a Party will not be aware how they are required to vote on a given occasion, when any important matter comes before the House.

16. Nevertheless, a formal direction is usually given to ensure that every Member acts in accordance with the wishes and the directions of that Party, specially since the enactment of the Tenth Schedule.

17. The Hon'ble Supreme Court has observed in the decision of *Kihota Hollohon v. Zachilhu & Ors.* (AIR 1993 SC 412) that a direction as contemplated by para 2(1)(b) of the Tenth Schedule is required to be in writing and issued to the Members.

18. In my view, in construing the words, 'directions issued', which appear in para 2(1)(b) of the Tenth Schedule, it cannot be expected always that there will be signed receipt by the Members in acknowledgment of the actual service of the Whip on him or her. One has to consider the totality of circumstances and the plausibility of the case in

coming to a finding whether directions were in fact issued to a Member concerned.

19. After giving my anxious consideration to the materials before me and considering the fact that the Respondent has admitted that he was present at the meeting of the party on 20 July, 2008, a day prior to the discussion on the Motion and that he was approached inside the House when his vote was not initially recorded, by the senior Members of the BJP and there was wide publicity of the matter and of the stand taken by the BJP to which the Respondent belongs, I am inclined to hold that the Respondent had been issued direction to be present in the House to take part in the Discussion and to vote against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers. It is difficult to accept the contention of the Respondent that although he was present at the Party meeting held on 20 July, 2008, he did not follow what had transpired at the said meeting because he did not know Hindi.

20. As the Speaker, my primary obligation is to ascertain the relevant facts as has been held by the Hon'ble Supreme Court. Having come to the conclusion that the Respondent has voted contrary to the direction of his party, the act of the Respondent comes within the purview of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution and I decide accordingly.

21. Thus, I hold that the Respondent Dr. H.T. Sangliana, an elected Member of Lok Sabha from Bangalore North (Karnataka) Constituency, has incurred disqualification under paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution of India by reason of his voting in favour of the Confidence Motion, moved by the Hon'ble Prime Minister of India, at the voting held on 22 July, 2008.

22. Thus the Respondent stands disqualified from continuing as a Member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant.

Sd/-

SOMNATH CHATTERJEE  
SPEAKER, LOK SABHA "

NEW DELHI

Dated the 3 October, 2008

[No. 46/18/2008-T]

P.D.T. ACHARY, Secy. General